

प्रेषक,

डा० रणवीर सिंह
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,

सेवा में,

- 1-आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून ।
- 2-जिलाधिकारी,
उधमसिंह नगर/हरिद्वार/चम्पावत/
देहरादून/पौड़ी/नैनीताल ।
- 3-संभागीय खाद्य नियंत्रक,
गढ़वाल संभाग, देहरादून/
कुमायूँ संभाग, हल्द्वानी ।

- 4-वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक,
भारतीय खाद्य निगम,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- 5-निदेशक मण्डी परिषद,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी ।
- 6-प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-2

विषय:- खरीफ-खरीद सत्र 2008-09 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद।

दिनांक : देहरादून : 15, दिसम्बर, 2008

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 127भा0स0/08-XIX-2/खरीफ-खरीद/41 खाद्य/2008 दिनांक 30 सितम्बर, 2008 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत करना है, कि, निदेशक, (पॉलिरी) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 170(1)/2008-पीवाई-1 दिनांक 21 अक्टूबर, 2008 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अन्य राज्यों के अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य में खरीफ-खरीद सत्र 2008-09 में भारत सरकार द्वारा धान कॉमन/ग्रेड-ए के न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः 850 एवं 880 प्रति कुन्तल पर रु० 50.00 प्रति कुन्तल की दर से प्रोत्साहन बोनस की धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की गयी है, कि, राज्य सरकार उक्त प्रोत्साहन बोनस की धनराशि रु० 50.00 (पचास रुपये मात्र) प्रति कुन्तल को सभी प्रकार के कर्षों से मुक्त रखेगी।

2. इस सम्बन्ध में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 692/XXVIII(8)/वाणिज्य कर(वैट)/2008 दिनांक 05 दिसम्बर, 2008 एवं कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1087/XIII-II/20(1)/06 दिनांक 02.12.2008 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में गुड़ी यह कहने का निदेश हुआ है, कि, भारत सरकार द्वारा खरीफ-खरीद सत्र 2008-09 में धान की खरीद हेतु निर्धारित उपर्युक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त स्वीकृत की गयी रु० 50.00 प्रति कुन्तल प्रोत्साहन बोनस की धनराशि को राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्तानुसार आशेषित किये जाने वाले कर्षों से मुक्त रखा जायेगा।

3. भारत सरकार द्वारा स्वीकृत उपर्युक्त प्रोत्साहन बोनस की धनराशि का भुगतान उनके उपर्युक्त पत्र दिनांक 21.10.2008 तथा पत्र संख्या 170(1)/2008-पीवाई-1 दिनांक 23 अक्टूबर, 2008 (छायाप्रति संलग्न) में दिये गये निर्देशानुसार ही सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उपर्युक्त के सम्बन्ध में गुड़ी यह भी कहने का निदेश हुआ है, कि, खरीफ-खरीद सत्र 2008-09 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद सम्बन्धी उक्त नीतिगत शासनादेश दिनांक 30 सितम्बर, 2008 के विन्दु संख्या- 2-(1) धान का मूल्य एवं गुणनिर्दिष्टियां, में

उल्लिखित धान की श्रेणी के सम्मुख मूल्य रुपये प्रति कुन्तल को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। उक्त शासनादेश को अन्य सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
5. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सभी सम्बन्धित से सुनिश्चित कराते हुए शासन को शीघ्र अवगत करा जाये।

भवदीय,

(डा० रणदीर सिंह)
सचिव।

संख्या 5/3 (1)/08-XIX-2-41 खा०/08 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
2. सचिव, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, (पॉलिसी) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्र संख्या 170(1)/2008-पीवाई-1 दिनांक 21 अक्टूबर, 2008 एवं 23 अक्टूबर, 2008 के सन्दर्भ में।
6. क्षेत्रीय प्रबन्धक, सी०डब्लू०सी०/एस०डब्लू०सी०, उत्तराखण्ड।
7. वरिष्ठ संभागीय वित्त अधिकारी, गढ़वाल संभाग, देहरादून/कुमायूँ संभाग, दलदानी।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०, देहरादून।
9. निजी सचिव, खाद्य मंत्री को मा० खाद्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
10. तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. माल फाइल।

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव।

Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution

Kind Attn: Sri P.D. Agarwa

Krish Bhawan, New Delhi.
Dated: 21st October, 2008.

To:

1. Chairman & Managing Director, FCI, New Delhi.
2. The Principal Secretary (Food) Government of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Chandigarh, Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Nagaland, Orissa, Punjab, Pondicherry, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal and Andaman & Nicobar Islands.

Subject: Incentive Bonus for paddy procurement during Kharif Marketing Season (KMS) 2008-09.

Sir,
I am directed to state that the Government of India has decided to give an incentive bonus of Rs 50 per quintal for procurement of paddy during KMS 2008-09 over and above the MSP of Rs. 850 per quintal and Rs. 880 per quintal in respect of Common and Grade 'A' varieties of paddy respectively. This will be subject to the condition that State Government shall fully exempt this bonus amount from all state taxes and levies. The incentive bonus will be applicable during the entire procurement period in KMS 2008-09.

2. The State Governments shall ensure that the bonus amount is paid to the farmers whose paddy is purchased by the State agencies during the entire KMS 2008-09.

3. Necessary instructions/orders may be issued to the concerned Procuring Agencies to implement the above decision of the Government.

Yours faithfully,

(RAVIKOTA)
DIRECTOR (POLICY)
Tel: 23389436

Copy to:-

1. The Economic & Statistical Adviser, Deptt. of Agri. & Co-op., Krish Bhawan, New Delhi.
2. JS(P&FCI)/JS(BP&PD)/JS(Storage)/JS(Implex EOP& CVOP)/Director(P)
3. Director(FCI)/DD(Movt.)/Director (Fin)/Director(BP)/Dir(PD)/JC(S&R)
4. Information Officer, Deptt. of Food & Public Distribution, Shastri Bhawan, New Delhi
5. PS to M/o (CA, F&PD) PS to MOS(F&PD)
6. PS to Secretary (F&PD), PPS to AS&FA,
7. US(PY-I)/JS(PY-II)/US, FCI, New Delhi.

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including dates like 21/10/08 and various initials.

वित्त विभाग

दिनांक: देहरादून: दिसम्बर 5, 2008

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है।

अतएव, अब, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (6), सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल सहर्ष आदेश करते हैं कि इस अधिरूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से रो भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा खरीद मार्केटिंग स्कीम (केएमएसओ), 2008-09 के दौरान धान की खरीद के लिये नियत समर्थन मूल्य (एमएसओएफओ) के अतिरिक्त दी जाने वाली प्रोत्साहन बोनस की धनराशि पर कोई कर उद्ग्रहित नहीं किया जाएगा। ऐसी धान से निर्मित चावल की बिक्री पर भी प्रोत्साहन बोनस की राशि की सीमा तक कोई कर उद्ग्रहणीय नहीं होगा।

(आलोक कुमार जी.)
प्रमुख सचिव, बिहार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

2-निदेशक, गुदण एवं लेखन सामग्री उपलब्धता के लिए प्रेषित।

2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रुड़की को सम्प्रोक्त अधिसूचना के अन्तर्गत अनुवाद सहित इस आशय से प्रेषित कि इसको अन्तर्गत सूची में सूचित है।

अनुवाद सहित इस आशय से प्रेषित कि इसको उत्तराखण्ड गजट में प्रकाशित करके इसकी 250, 250 प्रतियां वित्त अनुभाग-8 में आवेगान् उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
3- गार्ड फाईल है।

3. ମାଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଜେଇ ଡେଇଁ ।

आज्ञा से
C. S. Jammwal
(सीओएसओमालवा)
अध्यापक, विद्या

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 692/XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/ 2008 dated 5 December, 2008 for general information.

Government of Uttarakhand

VITTA VIBHAG

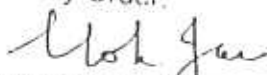
NO. 692/XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/2008
Dehradun :: Dated : 5 December, 2008

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest,

NOW, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to order that with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, no tax shall be levied on the incentive bonus amount to be paid by the Government of India, Department of Food & Public Distribution for procurement of paddy during Kharif Marketing Season (K.M.S.) 2008-09 over and above the procurement price (M.S.P.) fixed for the purchase of paddy. No tax shall also be levied on sale of rice manufactured from such paddy to the extent of incentive bonus amount.

By Order,



(ALOK KUMAR JAIN)

PRINCIPAL SECRETARY FINANCE

प्रेषक,

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,
रुद्रपुर।

देहरादून : दिनांक : २ नवम्बर, 2008

विषय:- खरीफ सत्र 2008-09 में भारत सरकार द्वारा धान कॉमन तथा ग्रेड-ए के लिए
रु० 50.00 प्रति कु० प्रोत्साहन बोनस को लेवी से मुक्त रखने विषयक।
महोदय,

उपरोक्त विषयक निर्देशक (पालिशी) उपरोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं०- 170(1)/2008 पी०वाई०-1 दिनांक 21 अक्टूबर, 2008 की प्रतिलिपि संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्यक निवारोपशान्त शासन द्वारा घान कॉमन एवं ग्रेड 'ए' की खरीद पर भारत सरकार के उक्त पत्र में उल्लिखित अवधि के लिए दिये जाने वाले प्रोत्साहन योजना की धनराशि रु० 50.00 प्रति कु० पर मण्डी शुल्क एवं विकास सेरा आरोपित न किए जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया तदनुसार कार्यवाही करने का काम करें।

संलग्नः— यथोपरि

$$2\{e\}e_1\}^2,$$

(वि.मो.क.को.नेमा)
राजिना

संख्या- 1067/XIII-II/20(1)/2006 तददिनांकित

महिलिणि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

पत्र सं० 134/08-XIX-2/71 स्वा.सं/2008 दिनांक 31 अक्टूबर, 2008 के संदर्भ में।

2. गान्धेय पञ्चावली ।

ਮਾਝਾ ਸੇ

(आ० शैलेश कुमार पन्त)
अनुराधित

1437170(10)/08. XIX. 2/08

No. 170(1)/2008-Py.
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution

Krishi Bhawan, New Delhi,
Dated 23rd October 2008

To

The Principal Secretary (Food),
Government of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh,
Chandigarh, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir,
Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur,
Meghalaya, Nagaland, Orissa, Punjab, Pondicherry, Rajasthan, Sikkim, Tamil
Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal and Andaman & Nicobar
Islands.

Subject: Payment of Incentive Bonus for paddy procured during Kharif Marketing
Season (KMS) 2008-09.

Sir,

I am directed to draw your attention to this Department's letter of even
number dated 21.10.2008 for payment of incentive bonus of Rs. 50 per q of paddy to
farmers over and above MSP during the KMS 2008-09 and to state that the incentive
bonus will also be applicable to paddy purchased by millers for delivering levy rice.

2. The incentive bonus will be applicable for the entire KMS 2008-09.
3. State Governments should ensure that bonus is paid to all farmers who have sold
paddy to rice millers/state agencies/FCI in KMS 2008-09 up to 21.10.2008 as well.
Suitable instructions for verification of this may be issued by State Governments
under intimation to FCI.
4. The bonus amount shall be fully exempted by the State Governments from all State
levies and taxes on paddy as well as rice.

Yours faithfully,

(Dr. RAVI KOTA)
Director (Policy)
Tel: 2338 9436

Copy to:

1. Chairman & Managing Director, FCI, New Delhi for necessary action.
2. The Economic & Statistical Adviser, Department of Agriculture & Cooperation, New Delhi.

Copy also to:

1. JS(P&FCI)/ Adviser (Cost)/Director(P)
2. Information Officer, Dept of Food & PD, Shastri Bhawan, New Delhi.
3. PS to MoCAF&PD, PS to MoSCAF&PD
4. PS to Secretary (F&PD), PPS to AS&FA
5. US (Py-I), US (PY-III), US (FC A/Cs/IS (Fin)/ Control Room, FC A/Cs/Policy-III.

31/11/08
D.S(F)

31/11/08

31/11/08

S.C. 2
17/11/08